नगर निगम ने सील की बीसियों इमारतें, पर किसकी कमाई के लिए?

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते रविवार को, छुट्टी का दिन होते हुए भी नगर निगम द्वारा चलाये गये विशेष अभियान के तहत एनआईटी नम्बर 1,3 व 5 में 20 से अधिक बहुमंजिला इमारतें सील कर दी गयी।

सवाल ये पैदा होता है कि यह सीलिंग है क्या चीज़? क्या इसके बाद इमारत गिरा दी जायेगी? या फ़िर यह भवन निर्माता को दबाव में लेकर सौदेबाज़ी करने का एक बेहतर हथियार है? बीते वर्षों में शहर भर में जो सैकड़ों इमारतें सील हुई हैं उनका क्या हुआ? वे सब सही सलामत इस्तेमाल में आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सेक्टर 7-10 की मार्केट कई बार सील हो चुकी, कई बार उन दुकानों के सामने रुकावटें भी खड़ी की गई उसके बावजूद आज भी वे तमाम दुकानें सुचारु ढंग से अपना कारोबार कर रही हैं। इसी तरह एनआईटी के तमाम बाजारों में अनेकों दुकानें सील की गई थीं जो आज खुली हुई हैं।

इमारतों को सील करने का प्रचार तो पूरे ढोल-धमाके के साथ किया जाता है, परन्तु उनकी सील लोगों ने कब स्वयं हटा ली या नगर निगम ने किस आधार पर उन सीलों को हटाया, इस बाबत नगर निगम हमेशा खमोश रहता है। अवैध बता कर जिस इमारत को सील किया जाता है वह कोई एक-दो दिन में तो बन कर खड़ी हो नहीं जाती, उसके बनने में महीनों व साल लग जाते हैं। निर्माण के दौरान नगर निगम कौन सी अफ़ीम खा

कर सो रहा होता है? क्यों नहीं पहली ईंट लगते ही निगम हरकत में आता? यह बात मानने को कोई तैयार नहीं कि निर्माण शुरू होने का निगम को पता ही नहीं चलता। दरअसल हर निर्माण शुरू ही निगम अधिकारियों की मिलीभगत एवं हिस्सेदारी में होता है।

बहुत गरजने-बरसने के बाद निगमायुक्त यशपाल यादव ने जो उक्त इमारतें सील की हैं वे बहुत जल्दी ही खुल जायेंगी। इनके नक्शे भी पास हो जायेंगे, निर्माण में किये गये उल्लंघनों को कम्पाऊंड करके अवैध निर्माण को वैध कर दिया जायेगा। जाहिर है यह सब काम मुफ्त में तो होता नहीं, इसके लिये अच्छी-खासी सौदेबाज़ी एवं लेन-देन होता है। यदि यही सब काम इमारत के निर्माण से पहले हो जाये तो निगम में बैठे मगरमच्छ क्या खायेंगे? इन मगमच्छों के पालन-पोषण के लिये हल्की-फुल्की तोड़-फ़ोड़ व सीलिंग का नाटक करना जरूरी होता है।

एनएच 3 में बनी कुछ अवैध इमारतों की तोड़-फ़ोड़ का नाटक करने जब निगमकर्मी पहुंचे तो क्षेत्र का पूर्व पार्षद मनोज नासवा अड़ कर खड़ा हो गया और तोड़-फोड़ नहीं करने दी। एक नासवा ही नहीं लगभग सभी पार्षदों का यही धंधा है। और तो और क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा भी प्राय: अवैध बिल्डरों के पक्ष में खड़ी नजर आती हैं।

यहां समझने वाली बात यह है कि जब पार्षदों व विधायक को तोड़-फोड़ के विरोध में खड़े होना पड़ता है तो ये सब लोग मिलकर निगम द्वारा नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल क्यों नहीं बनाते? यही तो समझने की बात है, यदि सब काम स्वत: एवं सुचारु रूप से होने लगें तो इन नेताओं की दुकानदारी फ़िर कैसे चल पायेगी? इसलिये मौजूदा व्यवस्था इन सभी नेताओं को माफ़िक आ रही है।

जल-भराव के कारण है, निदान नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) चार बूंद पानी की बरसी नहीं कि शहर में सैलाब आ जाता है। रेलवे अंडरपास डूब जाते हैं। सड़को पर ट्रैफ़िक जाम हो जाता है। ऐसे में बरसात जैसा कुदरत का अनमोल तोहफ़ा अभिशाप नज़र आने लगता है। इसके लिये बरसात नही बल्कि मूर्ख, लालची व भ्रष्ट योजनाकार एवं शासन-प्रशासन जिम्मेवार हैं। इनकी नालायकी एवं आपा-धापी के चलते विकास का जो मॉडल बनाया गया है, वह जिम्मेवार है।

पानी अपना रास्ता सदैव खुद बनाता आया है, लेकिन जब विकास के नाम पर उसका रास्ता रोक दिया गया तो जल भराव की स्थिति बन खड़ी हुई। इसी शहर में 150 से ऊपर छोटे-बड़े तालाब होते थे जिनमें बरसाती पानी बहकर जमा हो जाता था। इसके चलते भू-जल स्तर भी बना रहता था। परन्तु लालच एवं भ्रष्टाचार ने पहले तो इन तालाबों को सीवर तथा मलबे से भर कर सड़ाया और फ़िर बेच खाया। ऐसे में बरसाती पानी जाये तो जाये कहां? इसकी निकासी के लिये करोड़ों रुपये खर्च करके जो भूमिगत नाले बनाये गये थे वे केवल कागजों तक ही सीमित रह गये।

अब भी यदि अक्ल से दुश्मनी न हो और ईमानदारी से काम करने की नीयत हो तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिये सेक्टर 14 में मार्केट के सामने वाली, करीब आधा किलो मीटर लम्बी सड़क पर जरा सी बारिश में सवा फुट तक पानी खड़ा हो जाता है। करीब दस साल पूर्व जब इस सड़क को सीमेंट कंक्रीट का बनाया गया तो यह साथ लगते पार्क से करीब डेढ़ फुट ऊंची हो गई। इसके परिणामस्वरूप बरसात का सारा

पानी बहकर पार्क में भरने लगा और सड़क पर एक बूंद पानी न रहता। एक-दो दिन में पार्क का सारा पानी ज़मीन में उतर जाता।

इसे और जल्दी ज़मीन में उतारने के लिये दो रेन हार्वेस्टर सिस्टम भी लगाये गये थे। जिनमें आज तक एक बूंद पानी की नहीं उतर सकी है और न ही कभी उतरेगी क्योंकि वे बनाये ही केवल बिल पास करके कमीशन खाने के लिये थे। पार्क में दूसरी समस्या सड़े हुए सीवेज़ से होने लगी। पार्क में बरसाती पानी तो ठीक परन्तु उसके साथ बहकर आने वाला सीवेज़ बुरी तरह से सड़ने लगा। सीवर लाइन चलाना तो निगम के बस का है नहीं लिहाजा पार्क में 60 लाख रुपये की मिट्टी भरा कर समस्या का समाधान कर दिया गया। परिणामस्वरूप अब फ़िर से इस सड़क पर एक से सवा फुट तक पानी खड़ा हो जाना आम बात हो गई है।

अब करने वाला काम जो इस शासन-प्रशासन के बस का नहीं है, एक तो सीवर लाइनों को सुचारु करे जो ये कभी कर नहीं सकते। यदि इसे सुचारु कर लें तो सेक्टरों के तमाम पार्कों को सड़क से नीचा करके सारा बरसाती पानी उनमें लिया जाय और सही ढंग के रेन हार्वेस्टर लगाये जायें। वैसे खट्टर महोदय ने करीब तीन साल पहले इस शहर में 1000 रेन हार्वेस्टर लगाने की बात कहीं थी, लेकिन आज तक उनमें से कोई एक भी कहीं लगा हो, देखा-सुना नही गया।

स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल से मरीज़ त्रस्त, सरकार मस्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले भर में डॉक्टरों के अलावा 1100 अन्य स्वास्थ्यकर्मी सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत हैं। इनमें से केवल 400 कर्मचारी नियमित एवं पक्की नौकरी में हैं जबकि शेष 700 ठेकेदारी, जिसे एनएचएम का नाम दिया गया है, के तहत कार्यरत हैं। शहर के विस्तार एवं बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यहां कम से कम 2500 स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता है।

अपनी जनविरोधी नीतियों के चलते सरकार ने बीते कई वर्षों से नई भर्तियां पूरी तरह से बंद कर रखी हैं। सेवा निवृत होने से रिक्त हुए स्थानों को ठेकेदारी व्यवस्था से भरने की नीति केवल इसलिये अपनाई जा रही है कि ऐसे कर्मियों का जम कर शोषण किया जा सकता है। इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की अपेक्षा मात्र एक चौथाई वेतन पर ही रखा जाता है। इसके अलावा इन्हें जब मर्जी काम से हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं इन्हें पेंशन व अन्य कोई सेवा लाभ भी नहीं मिलता। अपनी वेतन वृद्धि व सेवा शर्तों में सुधार को लेकर ये लोग हड़ताल पर चल रहे हैं।

1100 कर्मियों में से जब 700 कर्मी हड़ताल पर होंगे तो पहले से ही चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं का जो दीवाला निकला है उससे वे गरीब मरीज़ त्रस्त हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि निजी स्वास्थ्य सेवायें इतनी महंगी हैं कि उन लोगों के वश की नहीं। जाहिर है ऐसे में, जब बीमारियों का सीजन चल रहा हो तो जनता का एक बड़ा वर्ग भारी मुसीबत में फंस कर रह गया है। गर्भवती एवं प्रसव वाली महिलाओं के लिये तो यह संकट और भी भारी हो गया है।

दरअसल इन हड़ताली कर्मियों का उद्देश्य मरीज़ों को दुखी करना नहीं है, वे तो केवल इसके द्वारा सरकार पर दबाव बना कर अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। मरीजों को सेवायें देने का दायित्व सरकार का है न कि किसी व्यक्ति विशेष का। जनता को सेवायें प्रदान करने के लिये सरकार आवश्यकतानुसार कर्मियों की भर्ती करती है जो अपनी सेवाओं के बदले वेतन एवं भत्ते आदि लेते हैं। लेकिन बेईमानी की नींव पर खड़ी सरकार हर तरह से प्रयास करती है कि सस्ते से सस्ते में कर्मियों को काम पर लगाकर खानापूर्ति की जाये।

इन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की स्थिति में मरीजों को होनेवाली परेशानी के लिये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है न कि कर्मी। लेकिन बेशर्मी पर उतरी सरकार को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि जिन लोगों को सेवा देना उसका दायित्व है और वह सेवा नहीं दे पा रही है। सेवा के आभाव में लोग मरते हैं तो मरें उसकी बला से।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।